1967 से रिजर्व बैंक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को अर्थात् निर्यात, कृषि-सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं को छोटे पैमाने के उद्योगों को बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने को बढ़ावा देने के लिये, पुनर्वित्त-योजना में समय समय पर कुछ रियायतें शामिल करता रहा है। रिजर्व बैंक द्वारा, पैकिंग-ऋण से सम्बद्ध पुनर्वित के सम्बन्ध में उपलब्ध लाभों का क्षेत्र विस्तृत करने के लिए हाल में कार्य-प्रणाली सम्बन्धी आवश्यकताओं में फेर-बदल किये जाने के सिवाय, पुनर्वित-योजना में हाल में और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सामान्यतः बक निर्यातकों को, विदेशी खरीदारों द्वारा उनके नाम खोले गये साख-पत्रों (लेटर्स आफ क्रेडिट) या निर्यात के पक्के आर्डरों के आधार पर पैकिंग-ऋण देते हैं और इन ऋणों का शोधन तत्सम्बन्धी निर्यात बिलों के अन्तरण (नेगोशियेशन) द्वारा किये जाने की प्रत्याशा की जाती है। बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा सलाह दी गयी है कि पैकिंग-ऋण का का लाभ (क) ऐसे निर्यातकों को जिनके नाम साख-पत्र या निर्यात के पक्के आर्डर न हों, जैसे खनिज और धातु व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम के, जिनके जरिये निर्यात किया जाता है, सम्भरकों को, (ख) संघ (कंसार्शियम) के प्रबन्ध के अधीन निर्यात के लिए माल भेजने वाले सब-कांट्रेक्टरों को, और (ग) "कन्साइनमेंट" के आधार पर नियोजित चाय जैसी वस्तुओं के निर्यातकों को भी दिया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक ने उन मामलों पर भी गुण-दोष के आधार पर विचार करने की पेशकश की है जिनमें शर्तों को पूरा करना सम्भव न हो, पर जिनमें लेन-देन अन्यथा किसी भी प्रकार के पैकिंग ऋण जैसा हो।

निर्वाह व्यय सूचकांक और मंहगाई भता

8783. **श्री मधु लिमये** : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 के पहले नौ महीनों में निर्वाह व्यय सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ा कर मूल्य वृद्धि को कितने प्रतिशत पूरा कर दिया है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वित्तीय वर्ष 1967-68 के पहले नौ महीनों के लिये अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1949-100) और इसका 12 महीनों का औसत नीचे दिया गया है :—

	मासिक मूल्य सूचकांक	वार्षिक औसत
अप्रैल, 1967	202	197.92
मई, 1967	206	195·00
जून 1967,	211	197.17
जुलाई, 1967	213	199.25
अगस्त, 1967	215	201.33
सितम्बर, 1967	214	203.25
अक्तूबर, 1967	217	205.33
नवम्बर, 1967	216	207.17
दिसम्बर, 1967	214	208.58

(ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को तब पुनरीक्षित किया जाता है जब अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1949-100) के 12 महीने के औसत में 10 अंकों की वृद्धि हो जाती है। गजेन्द्रगडकर आयोग ने निराकरण के लिए जिन प्रतिशत और दरों का सुझाव दिया है उनके अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में औसत सचकांकों 195 तथा 205 के अनुरूप वृद्धियां क्रमशः 1-6-1967 और 1-11-1967 से की गई हैं। इन दो मौकों पर पर औसत मूल्य सुचकांक में 10 अंकों की बढ़ोतरी होने पर जो निराकरण किया गया उसकी मात्रा नीचे दी गई है :—

वेतन श्रेणी रु०	निराकरण का प्रतिशत
70 और ऊपर, परन्तु 110 से नीचे	90 प्रतिशत
110 और ऊपर, परन्तु 150 से नीचे	60 ,,

150 और ऊपर, परन्तु 210 से नीचे 55 प्रतिशत
210 और ऊपर, परन्तु 400 से नीचे 45 ,,
400 और ऊपर, परन्तु, 450 से नीचे 25 ,,
450 और ऊपर, परन्तु 499 तक 24 ,,

राज्य सरकारों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

ग्वालियर में डीनेचर्ड स्पिरिट का बरामद किया जाना

8784. श्री रामावतार शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादन विभाग प्राधिकारियों ने ग्वालियर में मार्च तथा अप्रेल, 1968 में 1 ड्रम तथा 6 टिन डीनेचर्ड स्पिरिट बरामद की है; और

(ख) यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

Inauguration of Madras Refinery

8785. SHRI SITARAM KESRI : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether Government have approached the Shah of Iran to visit India for the inauguration of the Madras Refinery ;

(b) whether the Shah has accepted the invitation and if so when the Refinery is likely to be inaugurated ; and

(c) whether other foreign dignitaries have also been invited for the same and if so, the names thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGURAMAIAH) : (a) No. Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Compulsory Deposit Scheme

8786. SHRI SITARAM KESRI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total amount collected by Government under the Compulsory Deposit Scheme ;

(b) the interest which Government would have to pay to the depositors on the same ; and

(c) whether Government propose to give any incentive to such depositors who would like to invest their deposits in Government bonds or other form of Government savings ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The amount collected in 1963-64 and 1964-65 was Rs. 39.5 crores. However, consequent on repayments in the case of Employees' scheme and other premature repayments the amount outstanding at the end of last year was nearly Rs. 30 crores.

(b) Simple interest at the rate of 4% per annum is payable on deposits remaining with Government.

(c) No such proposal is at present under consideration of Government.

Investment of Unit Trust Funds

8787. SHRI SITARAM KESRI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state the manner in which the funds of the Unit Trust of India are utilised and the agencies or firms that have been receiving or have received loans from the Unit Trust of India or the firms and agencies in which the funds of the Unit Trust of India are invested ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : The Unit Trust has no power to grant loans to industrial concerns. It is authorised under its regulations to invest, in any one individual company, upto a ceiling of 5 per cent of the total investible funds of the Trust or 10 per cent of the securities issued and outstanding of the company concerned, whichever is lower, though exception has been made in the case of first-mortgage